सूचना का अधिकार अधिनियम की स्थिति

13 वर्षों तक, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने नागरिकों को केंद्रीय और राज्य संस्थानों से जानकारी और डेटा प्राप्त करने में मदद की जो सार्वजनिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। आरटीआई अधिनियम किसी भी नागरिक को सरकार के पास मौजूद डेटा, दस्तावेजों और अन्य जानकारी तक पहुंच के लिए अनुरोध करने की अनुमति देता है। भारत के आरटीआई अधिनियम को आमतौर पर दुनिया में सबसे व्यापक सार्वजनिक रिकॉर्ड पहुंच कानूनों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, कार्यकर्ताओं को चिंता है कि प्रणाली को कम से कम प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बंद हो रहा है।

क्या आरटीआई अधिनियम में संशोधन किया गया है?

राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता कारणों से कुछ सूचनाओं को गुप्त रखने की अनुमति देने के अलावा, आरटीआई अधिनियम एक छूट देता है - यह सरकार द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है, जब तक कि ऐसा करने में कोई सार्वजनिक हित न हो।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने इस योग्य निषेध को पूर्ण निषेध में संशोधित किया। हालाँकि, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) ने तर्क दिया कि इससे राशन वितरण में 'सामाजिक ऑडिट' करना असंभव हो जाएगा। सामाजिक ऑडिट में, एक समुदाय के सदस्य को आरटीआई अनुरोध के माध्यम से राशन लाभार्थियों की एक सूची मिलती है, और व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करता है कि लाभार्थियों को वही मिला है जो उन्हें कागज पर मिला हुआ प्रतीत होता है। ऐसी भी चिंताएँ हैं कि शक्तिशाली सार्वजनिक अधिकारी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर इस व्यापक प्रतिबंध को लागू करके जवाबदेही से बचेंगे।

आरटीआई अधिनियम में पिछले संशोधनों ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को यह तय करने की एकतरफा शक्ति दी कि असंतोषजनक या अनुपस्थित आरटीआई प्रतिक्रियाओं के खिलाफ अपील सुनने वाले सूचना आयुक्त कितने समय तक सेवा कर सकते हैं और उनका वेतन क्या है।

आरटीआई अधिनियम को और कैसे कमजोर किया गया है?

आरटीआई अधिनियम ही वह एकमात्र तरीका नहीं है जिससे कार्यकर्ता देखते हैं कि इसके द्वारा शुरू की गई पारदर्शिता कमजोर हो गई है। आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधीनस्थ नियमों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, एक सार्वजनिक प्राधिकरण किस भुगतान पद्धति को स्वीकार कर सकता है, इसका निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य

भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) स्वीकार नहीं करते हैं, जो चेक होते हैं जिन्हें डाकघरों में खरीदा जा सकता है और भुगतान के रूप में आवेदन के साथ जोड़ा जा सकता है। आईपीओ आम तौर पर प्राप्त करने का सबसे आसान भुगतान तरीका है। अन्य भुगतान विधियां कम सुविधाजनक या अन्यथा बोझिल हैं - कोर्ट शुल्क स्टांप केवल अदालत में खरीदे जा सकते हैं, और 10 के डिमांड ड्राफ्ट के लिए प्रसंस्करण शुल्क की आवश्यकता हो सकती है जो उस राशि से दोगुनी से अधिक है।

सूचना आयोगों - केंद्र सरकार के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) - में धीमी नियुक्तियों ने भी आरटीआई ढांचे में विश्वास को कम कर दिया है, क्योंकि अपील की सुनवाई में महीनों या वर्षों का समय लग सकता है। उदाहरण के लिए, झारखंड एसआईसी में मई 2020 से अपील सुनने के लिए कोई आयुक्त नहीं है, जिससे अनिवार्य रूप से राज्य में आरटीआई अधिनियम के अप्रभावी प्रशासन के खिलाफ अपील करने की क्षमता निलंबित हो गई है।

ऑनलाइन आरटीआई के बारे में क्या?

आरटीआई आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल करने की अनुमति देने से काफी हद तक कुछ बाधाएं दूर हो जाती हैं - असामान्य वित्तीय साधन प्राप्त करने के बजाय, नागरिक केवल ऑनलाइन अनुरोध दर्ज कर सकते हैं और यूपीआई के साथ भुगतान कर सकते हैं। हालाँकि, कई राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नहीं है, और यदि है भी, तो कई राज्य सरकार निकायों के लिए पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होना आम बात है।

केंद्र सरकार का आरटीआई पोर्टल - जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था - भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। जबकि केंद्र सरकार के अधीन कई सार्वजनिक प्राधिकरण पोर्टल पर हैं, इस पर आवेदन दाखिल करना कठिन हो गया है। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर एक खाता होने से नागरिकों को डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक आवेदन पर अपना व्यक्तिगत विवरण भरने की अनुमति मिलती है। अब, हालाँकि, खाता बनाने की सुविधा गायब हो गई है, और साइट सभी उपयोगकर्ताओं को हर बार आवेदन दाखिल करने पर अपना विवरण नए सिरे से दर्ज करने के लिए बाध्य करती है। इसके अलावा, आवेदकों का पिछला डेटा पोर्टल के अंदर और बाहर रुक-रुक कर आ रहा है। अगस्त में, 2022 से पहले उपयोगकर्ताओं द्वारा दायर किए गए एप्लिकेशन का डेटा बिना किसी निशान के गायब हो गया और द हिंदू द्वारा इसकी रिपोर्ट करने के बाद, सरकार ने एप्लिकेशन को बहाल कर दिया।

आगे क्या?

आरटीआई के लिए संस्थानों और वेबसाइटों द्वारा उत्पन्न स्पष्ट संरचनात्मक समस्याओं से परे, सबसे बुनियादी स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एनजीओ के निदेशक वेंकटेश नायक ने सीआईसी की नवीनतम रिपोर्ट के विश्लेषण में कहा, अधिक से अधिक प्रथम अपीलें दायर की जा रही हैं। श्री नायक के अनुसार, यह इंगित करता है कि लोग सार्वजनिक अधिकारियों से प्राप्त होने वाली जानकारी से असंतुष्ट हो रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से आरटीआई अधिनियम को कमजोर करने की चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने जो नुकसान देखा है, वह केवल कानून के पाठ में बदलाव से नहीं है, बल्कि विभिन्न सरकारी तंत्रों में विभिन्न संस्थानों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने के तरीकों से भी हुआ है। अनुरोधों को आसानी से दर्ज करने और ऐसा करने के बाद जानकारी प्राप्त करने के रास्ते, और अपीलें गैर-कर्मचारी अपीलीय निकायों पर आती हैं।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधीनस्थ नियमों पर निर्भर है।
2. यह 2005 में लागू किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न ही 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of the Right to Information Act:

1. Implementation of the RTI Act is dependent on the subordinate rules made by the Central Government and State Governments.
2. It was implemented in 2005.

How many of the above statements are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : 'हाल के वर्षों में, यह चिंता जताई गई है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को कम प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बंद हो रहा है।' इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में सूचना के अधिकार अधिनियम की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में चर्चा करें कि कैसे और क्यों सूचना के अधिकार अधिनियम को कम प्रभावी बनाया जा रहा है।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।